

आका"वाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून उत्तराखण्ड)

सोमवार 23.06.2025

समय 1830

मुख्य समाचार :-

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
- सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक और कॉर्पोरेटिव विभाग नैनीताल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कांवड़ मेले से संबंधित सभी तैयारी समय से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई।

ओलंपिक दिवस मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन खेल भावना, एकता और शांति के मूल्यों को समर्पित है। ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि समर्पण, साधना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हुए हैं। भारत अब खेलों में केवल भागीदार नहीं, बल्कि विजेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को 'खेलभूमि' के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों, हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं।

ओलंपिक दिवस चम्पावत

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज चम्पावत जिले में विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर और खेलो इण्डिया साई सेंटर छमनिया, लोहाघाट में एथलेटिक्स, कूद, गोला फेंक और फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। खेलो इंडिया साई सेंटर के प्रभारी मोहन सिंह राणा ने बताया कि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने पर्यटन सचिव को राज्य के पर्यटन ढांचे को मजबूती प्रदान करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए योजनाएं तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव की तर्ज पर प्रदेश के हर जिले में दो गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय शैली और संस्कृति का पूरा ध्यान रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर घोषित दो अध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का शीघ्र चिन्हांकन कर कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही साहसिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नए डेस्टिनेशन विकसित करने पर बल दिया, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिल सकें। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में होमस्टे मॉडल प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और ग्रामीण पर्यटन के सामंजस्य से उत्तराखंड को एक आदर्श पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक और कॉपरेटिव विभाग नैनीताल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और डिजिटल सेवाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। बैठक में किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने, स्वयं सहायता समूहों को अधिक सहयोग करने और बैंकिंग सेवाओं को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव कांवड़ बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को कांवड़ मेले से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज कांवड़ मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने व्यवस्थित कांवड़ मेले में बाधक बनने वालों पर सख्ती करने और मेले के दौरान बड़े डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले के दौरान स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। बैठक में हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मेले के सफल संचालन के लिए की गई तैयारियों, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था आदि का प्रस्तुतिकरण दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांवड़ मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में बांटा गया है। बैठक में देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिलों की ओर से भी अपनी तैयारी और बजटीय आवश्यकताओं से अवगत कराया गया। गौरतलब है कि कांवड़ मेला 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा।

पंचायत चुनाव रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार द्वारा 11 जून को जारी आरक्षण संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अब तक पंचायत चुनाव में लागू हुए आरक्षण को शून्य मानकर इस वर्ष से नए सिरे से प्रथम आरक्षण लागू माना जायेगा।

न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की। न्यायालय ने पिछली सुनवाई में सरकार से 9 जून को जारी नियमावली और 11 जून को जारी आदेश पर जवाब मांगा था। जिसका सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।

वहीं, प्रदेश के पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि इसे शीघ्र जारी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बलिदान दिवस हल्द्वानी

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को डॉ. मुखर्जी के विचारों और योगदान से अवगत कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अब स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में उनकी जीवनी को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पहले से पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन अब शैक्षणिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को उनके विचारों और योगदान के बारे में जागरूक किया जाएगा। डॉ. रावत ने कहा कि आपातकाल के दौर और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग जैसे विषयों पर भी शिक्षण संस्थानों में जानकारी दी जाएगी, ताकि विद्यार्थी इतिहास के उन पक्षों से भी रुबरू हो सकें।